कर सकते हैं। अन्य शान्तिपूर्ण तथा रचनात्मक तरीकों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ फोरम, व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध से हम इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। सैनिक कार्यवाही जैसी चीजों की, जिनसे विश्व शान्ति को खतरा पैदा होता है, हमें हमेशा निन्दा करनी चाहिए लेकिन इसके साथ-साथ हमें राष्ट्रीय हित का ध्यान पहले रखना चाहिए। अतः प्रधान मन्त्री का वक्तव्य सराहनीय तथा सन्तुलित है।

Shri Gulam Mohammad Bakshi (Srinagar) : Mr. Speaker, Sir, we fought valiantly against the agressions committed on us by China and Pakistan in 1962 and 1965 respectively. At the same time we had expected that other countries should condemn these agressions by calling them what they were, i.e. aggressions. I feel we shall be accused of having a double standard in the international politics if we do not condemn the Soviet action by calling it an aggression.

During the course of our struggle for freedom, we were equally anxious about the freedom of other countries and we have always been a staunch supporter of the right of self-determination—the right of a nation to shape its destiny. We should condemn this hostile military intervention by Russia in the internal affairs of Czechoslovakia and prove that we still support the right of freedom of other countries.

The statement of the Prime Minister demanding the withdrawal of aggressive forces is not at all enough. She has not taken a clear stand on the issue. It is a challange for India and we have to respond to it, otherwise it will bring down our national honour and prestige in the eyes of other nations. We should, therefore, condemn this aggression by Soviet Russia on Czechoslovakia in clear and unmistakable terms.

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं नहीं समझता रूस का चैकोस्लोवाकिया के आन्तरिक मामलों में यह सैनिक हस्तक्षेप उचित है। फिर भी, सभा में यह मांग की गई है कि हमें चैकोस्लोवाकिया पर रूस के आक्रमण की स्पष्ट शब्दों में निन्दा करनी चाहिए। ऐसा सुझाव भी दिया गया है कि हमें चैकोस्लोवाकिया में ऐसी किसी सरकार को मान्यता नहीं देनी चाहिए जो उस देश की लोकप्रिय सरकार न हो।

मैं चाहता हूँ कि सदस्यों द्वारा इन दो मांगों के बारे में अपना निश्चित मत अथवा धारणा बनाये जाने से पूर्व प्रधान मन्त्री कुछ बातों का स्पष्टीकरण करें।

इस समय स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ दिन पहले श्री ब्रेजनेव के बीमार होने का समाचार मिला था। कल ही हमने ऐसा सुना कि रूस के प्रधान मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री ने त्यागपत्र दे दिये हैं। इन सभी बातों से यह सन्देह पैदा होता है कि सोवियत नेताओं के आपस में गंभीर मत-भेद है। क्या सरकार ने इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है ? क्या उसने मास्को स्थित अपने दूतावास से सम्पर्क स्थापित करके इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त की है ?

इसके बाद एक समाचार यह मिला कि सोवियत रूस और वारसा सन्धि वाले देशों के तत्काल हस्तक्षेप का कारण यह है कि चैकोस्लोवाकिया के श्रमिकों और वहाँ के बुद्धिजीवियों के बीच गंभीर संघर्ष चल रहा था। क्या सरकार ने प्राग स्थित अपने दूतावास से यह मालूम करने का प्रयत्न किया है कि क्या इस समाचार में कोई सच्चाई है और क्या यह सच है कि चैकोस्लोवाकिया के श्रमिक इस आकमण के प्रति काफी हद तक उदासीन थे।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री, तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : चैकोस्लोवाकिया की स्थिति पर वक्तव्य देते हुए कल मैंने यह कहा था कि मैं भारी दिल तथा गहरी चिन्ता के साथ ऐसा कर रही हूं और मैंने काफी सोच-विचार तथा परामर्श के बाद

अपने शब्दों का चयन किया था। इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जबकि सरकार जो कुछ कहती है अथवा करती है, उससे उस पर बहुत भारी उत्तरदायित्व आ जाता है। यह भी ऐसा ही एक क्षण है, बुद्धिमता इसी में है कि हम बड़ी सावधानी से चलें।

चैकोस्लोवाकिया तथा वहां के लोगों के साथ मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और व्यक्तिगत मैत्री है। कल मैंने चैकोस्लोवाकिया की सरकार तथा वहां के लोगों के लिये अपनी भावनाएँ-संसद की भावनाएं व्यक्त की थीं और यह आशा व्यक्त की थी कि चैकोस्लोवाकिया में फिर से सामान्य तथा विधिवत गठित सरकार बन सकेगी। हमें आशा है कि तर्क, विचार विमर्श तथा वाद-विवाद द्वारा मत-भेद अब भी सुलझाये जा सकते हैं लेकिन बल द्वारा नहीं, केवल इसी तरीके से कोई स्थायी समझौता किया जा सकता है। हमारा अब भी दृष्टिकोण यही है कि ऐसे राजनैतिक मतभेद तथा संघर्ष बल के माध्यम से नहीं सुलझाये जा सकते।

हमें चैक सरकार और दल-नेताओं की सुरक्षा तथा कल्याण की भारी चिन्ता है, जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमें खासतौर से चिन्ता है क्योंकि हम इन वर्षों में तनावों को कम करने तथा शीत-युद्ध के वातावरण को शान्त करने में लगे रहे हैं। चैकोस्लोवाकिया में सशस्त्र सेनाओं के प्रवेश की कार्यवाही से सारी स्थिति एक ही झटके में पलट गई है। इसने हमें तत्काल कई वर्ष पीछे फैंक दिया है मानो शांतिपूर्ण हल ढूंढने के लिये लोगों को निकट लाने तथा उनमें परस्पर संम्पर्क स्थापित करने के इस लम्बे काम को एकाएक नष्ट कर दिया गया है।

हम इस बात को अनुभव करते हैं कि विश्व में शान्ति के लिये यह चिन्ता का विषय है। माननीय सदस्यों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका अदा करे। हमारे देश कोसुरक्षा परिषद् का एक सदस्य होने का सम्मान प्राप्त है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अन्तर्गत सुरक्षा सम्बन्धी मामलों पर विचार करने का एकमात्र स्थान सुरक्षा परिषद् ही है। एक ऐसी सरकार के लिये जो सुरक्षा परिषद की सदस्य है, उन प्रश्नों पर जिन पर, वहां विचार-विमर्श किया जाना है अपनी स्थिति स्पष्ट करना उचित नहीं हो सकता।

चैकोस्लोवाकिया में जो कुछ हुआ है उस पर हमने अपनी प्रतिक्रिया निर्भय होकर तथा निस्संकोच होकर व्यक्त की है। मैं इस सभा को यह आश्वासन देना चाहूँगी कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र का, जिस पर मानव जाति की शान्तिपूर्ण विश्व के निर्माण की आशाएं निहित हैं, सदैव पालन करेंगे। हम चैकोस्लोवाकिया के चार्टर अधिकारों की हर प्रकार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे।

सुरक्षा परिषद् के सदस्य के नातें हमने कुछ बुनियादी तथा मूल सिद्धान्त स्वीकार किये हैं जिनका हम इन वर्षों में पालन करते रहे हैं। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक राज्य को अपने भविष्य तथा भाग्य का फैसला करने के लिए स्वच्छन्द और स्वतन्त्र छोड़ दिया जाना चाहिए और उसके आन्तरिक मामलों में कोई वाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। निर्णय करने के लिए बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और विचारधारा तथा सामाजिक व्यवस्था में मतभेद दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का कारण कभी नहीं बन सकते। ये कोई नये सिद्धान्त नहीं हैं, जिन्होंने कठिन तथा विभिन्न परिस्थितियों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भारत के मार्ग का अनुसरण किया है, वे यह स्वीकार करेंगे कि ये सिद्धान्त हमारी विदेशी नीति की नीव हैं। इन्हीं सिद्धान्तों के सहारे हमने परिस्थितियों को आंका है और उन पर अपना निर्णय लिया है और आगे

भी ऐसा करते रहेंगे। वर्तमान स्थिति ऐसी है जैसे पहाड़ से चट्टान गिरता है क्योंकि संसार इस संकट से या तो सम्मानपूर्वक तथा शान्तिपूर्वक निकल जायेगा और आगे बढ़ेगा या फिर हमें विनाशकारी स्थिति से गुजरना पड़ेगा जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के अन्त में इस संसार को हिला दिया था अथवा लगभग नष्ट कर दिया था।

हमने हमेशा तनाव को कम करने के प्रयत्न किये हैं, अब हमारा इसमें एक निहित स्वार्थ है। सभी विकासशील देशों की तरह हमें भी अपने विकास और अस्तित्व को कायम रखने के लिए शान्ति की आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थिति में उन सेनाओं को तत्काल वापस बुलाना आवश्यक है जो वहां प्रवेश कर चुकी हैं ताकि चैकोस्लोवाकिया की जनता बिना किसी हस्तक्षेप के तथा तनाव रहित वातावरण में अपने भविष्य का निर्णय करने के लिए स्वतन्त्र हो। चैकोस्लोवाकिया तथा उसके पड़ौसी राज्यों के बीच जो भी समस्याएं हों उन्हें शान्तिपूर्वक निपटाया जाना चाहिए ओर न कि बल प्रयोग के माध्यम से। हमने चैकोस्लोवाकिया और सोवियत गणराज्य के राजदूतों तथा वारसा सन्धि वाले देशों के राजदूतों को इस मामले में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से बता दिया है। हम अन्य राज्यों के राजदूतों से भी सम्पर्क कायम किये हुये हैं।

हम बहादुर और साहसी चैक जनता के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करने में किसी से पीछे नहीं हैं। इस दुखद परिस्थिति का जिस शान्ति तथा गौरव से वे मुकाबला कर रहे हैं, उसकी भी हम भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं और हमें इस बात का विशेषकर पता है कि उन्होंने जिस मार्ग को चुना है वह सत्याग्रह का मार्ग है।

जहाँ तक रूस में व्यक्तियों के बीच और चैकोस्लोवाकिया में श्रमिकों तथा बुद्धिजीवियों के बीच संघर्ष के प्रश्न का सम्बन्ध है, हमारे पास इन अफवाहों के बारे में कोई प्रमाणित समाचार अथवा जानकारी नहीं है सिवाय इसके कि कुछ दिन पहले "प्रावदा" में किसी मोटर-गाड़ी उद्योग के 90 श्रमिकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने समाजवाद को बचाने के लिये कुछ मदद मांगी थी। फिर भी, दो दलों के बीच किसी प्रकार का मतभेद बिलकुल संभव है—चाहे जो भी हो उसे दूर करना उनका अपना काम है।

वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर है। हम चाहते हैं कि हम ऐसी स्थिति में हों जब कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में सचमुच अपनी भूमिका अदा कर सके। चैक जनता के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है और हम उसकी प्रशंसा करते हैं।

श्री मी० रु० मसानी : हम इस विषय में सभा का सर्वसम्मत मत चाहते हैं। यदि सरकार अपने दल की सदस्या श्रीमती सुचेता कृपालानी का संशोधन स्वीकार कर ले तो हम सब इसके पक्ष में मत देंगे।

श्री रा० ढो० भण्डारे : प्रधान मंत्री के भाषण के पश्चात् मैं नहीं समझता मेरे लिये कुछ कहना आवश्यक है। मैं नहीं समझता कि प्रधान मंत्री ने कोई अस्पष्ट बात की है। यह कहना सर्वथा गलत है कि प्रधान मंत्री ने सोवियत संघ की कार्यवाही को माफ कर दिया है अथवा उनके वक्तव्य में अपराधपूर्ण मौन है। उनका वक्तव्य स्पष्ट है और परिपूर्ण है।

हमें चैक जनता को यह बता देना चाहिए कि विदेशी राष्ट्रों से छुटकारा पाने तथा लोकतंत्र की स्थापना करने और शान्ति, समृद्धि तथा समाजवाद के लिये कार्य करने के उनके प्रयत्नों में हम उनके साथ हैं।